

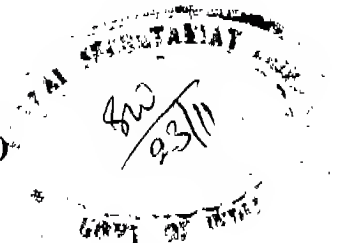


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 405]
No. 405]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 1989/श्रावण 10, 1911
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 1989/SRAVANA 10, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिमूचनाएँ

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1989

सं. 213/89-सीमाशुल्क

भा.का.नि. 733(प्र) - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, खपने वाले माल को जब उसका भारत सरकार के अन्तर्गत विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी लोक निधिक अनुसंधान संस्थान द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आयातकर्ता" कहा गया है), भारत में आयात किया जाए, तो:-

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 57) की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से; और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से,

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देनी है, अर्थात्:-

(1) तकनीकी विकास महानिदेशालय, भारत सरकार का कोई अधिकारी, जो औद्योगिक महाहकार की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रत्येक मामले में यह प्रमाणित करता है कि ऐसे खपने वाले माल का जिसके संबंध में इस अधिमूचना के अधीन छूट का दावा किया गया है, वित्तमार्ग भारत में नहीं किया जाता है और ऐसा प्रमाणपत्र निकासी के समय या ऐसी अवधि के भीतर जो महायुक्त सीमाशुल्क कालकटर पर्याप्त कारण दर्शाते हुए जाने पर प्रत्येक मामले में अनुमान करे, आयातकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है;

(2) आयातकर्ता से प्रशासनिक रूप से सम्बद्ध विभाग में भारत सरकार का कोई अधिकारी, जो उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रत्येक मामले में यह प्रमाणित करता है कि ऐसा खपने वाला माल, जिसके संबंध में इस अधिमूचना के अधीन छूट का दावा किया गया है, आयातकर्ता के अनुसंधान संबंधी प्रयासों के लिए अर्पित है और आयातकर्ता किसी

वाणिज्यिक क्रियाकलाप में नहीं लगा हुआ है और वह इस अधिसूचना के अधीन छूट की मंजूरी के लिए भिकाशित करता है और ऐसा प्रमाणपत्र निवासी के समय या ऐसी प्रवृत्ति के अंतर्गत जो महान्वय सीमाशुल्क कन्ट्रोल बर्तन कारण दक्षित किए जाने पर प्रत्येक मामले में अनुज्ञान करे, आयात-कर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

- (3) आयात करने वाली संस्था का प्रधान प्रत्येक मामले में यह प्रमाणित करता है कि ऐसे आने वाले माल का, जिसके संबंध में इस अधिसूचना के अधीन छूट का दावा किया गया है, केवल अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा और उसका किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए अधिष्ठाता—

- (क) "लोक-निधि अनुसंधान संस्था" से ऐसी कोई अनुसंधान संस्था अधिष्ठित है, जिसकी रक्षा में आबर्ली व्यव के 50 प्रतिशत से घट्यून का केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है ;
- (ख) संस्था के "प्रधान" से उसका निदेशक (चाहे वह किसी भी नाम से शात हो) अधिष्ठित है।

[फा.सं. 346/19/89-टीआरयू]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st August, 1989

NO. 213/89-CUSTOMS

G.S.R. 733(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts consumable goods, when imported into India by a public-funded research institution under the administrative control of the Department of Space or the Department of Atomic Energy of the Government of India (hereinafter called "importer"), from—

- (a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (57 of 1975); and
- (b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely :—

- (i) an officer of the Directorate General of Technical Development, Government of

India, not below the rank of Industrial Adviser certifies in each case that the consumable goods in respect of which the exemption is claimed under this notification are such as are not manufactured in India and such certificate is produced by the importer at the time of clearance or within such period as the Assistant Collector of Customs may, on sufficient cause being shown, allow in each case ;

- (ii) an officer of the Government of India not below the rank of Deputy Secretary in the Department administratively concerned with the importer certifies in each case that the consumable goods in respect of which the exemption is claimed under this notification are such as are required for the research activity of the importer and the importer is not engaged in any commercial activity and recommends the grant of exemption under this notification, and such certificate is produced by the importer at the time of clearance or within such period as the Assistant Collector of Customs may, on sufficient cause being shown, allow in each case ;

- (iii) the Head of the importing institution certifies in each case that the consumable goods in respect of which exemption is claimed under this notification shall be used only for the purposes of research and shall not be transferred to any other person.

EXPLANATION—

For the purposes of this notification, the expression—

- (a) "public-funded research institution" means a research institution in the case of which not less than fifty per cent of the recurring expenditure is met by the Central Government or the Government of any State or the administration of any Union Territory ;
- (b) "Head" of the institution means the Director thereof (by whatever name called).

[F. No. 346/19/89-TRU]

सं. 214/89-सीमाशुल्क

न.क.सि. 734(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1989 (1989 का 13) की धारा 35 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने यह समाधान

हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के निम्न मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 151/89-सीमाशुल्क तारीख 12 मई, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 266 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“267. संख्या 213/89-सीमाशुल्क, तारीख 1 अगस्त, 1989”

[फा.सं. 346/12/टी प्रारम्भ]

टी. प्रेम कुमार, उप सचिव

NO. 214/89-CUSTOMS

G.S.R. 734(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4)

of section 35 of the Finance Act, 1989 (13 of 1989), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 159/89-Customs, dated the 12th May, 1989, namely :—

In the Schedule to the said notification, after serial number 266 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely :—

“267. No. 213/89-Customs, dated the 1st August, 1989.”

[F. No. 346/19/89-TRU]

T. PREM KUMAR, Dy. Secy.

